साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 24-30 मार्च 2025 वर्ष-10, अंक-49

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

-खुलासा होने के बाद 74 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज, कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर की गई कार्रवाई

धान मिलिंग-फर्जी खरीदी में 46 करोड़ रुपए का घोटाला

मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन के कर्मचारी भी शामिल

मिलर, प्रबंधक, ऑपरेटर-कर्मचारी मोबाइल बंद कर हो गए फरार

14 करोड़ की धान बाजार में ही बेंची और 16 करोड़ की पोर्टल पर चढ़ाया

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश परिवहन विभाग का घोटाला सुर्खियां बटोर रहा है। विधानसभा में विपक्ष के नेता सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर धान मिलिंग और फर्जी खरीदी का 46 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है। जबलपुर जिले में धान की खरीदी, परिवहन और मिलिंग में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर इस फर्जीवाड़े में शामिल 74 लोगों के खिलाफ जिले के 12 थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। इस पूरे खेल में 13 कर्मचारी, 17 राइस मिलर, 25 सोसाइटी के 44 कर्मचारियों समेत 74 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी है। इधर, जिला प्रशासन की कार्रवाई को लेकर हड़कंप मचा रहा। इसकी भनक लगते ही मिलर्स, सोसाइटी प्रबंधक, कम्प्यूटर ऑपरेटर और कर्मचारी अपने मोबाइल बंद कर फरार हो गए। इस फर्जीवाड़े की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।

कागजों में खरीदी धान

मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन से जुड़े कर्मचारियों ने मिलर, सोसाइटियों के साथ मिलकर कागजों पर धान चढ़ाई, परिवहन किया और फर्जी रिलीज ऑर्डर काटे। करीब 30 करोड़ 14 लाख रुपए की धान कागजों पर खरीद ली गई। इसमें से करीब 14 करोड़ की धान जबलपुर के बाजार में ही बेंची गई और शेष 16 करोड़ की धान को आनलाइन पोर्टल पर चढ़ाया।

स्थानीय दलालों को बेची

ग्वालियर, उज्जैन, मुरैना, मंडला, मनेरी आदि स्थानों के मिलर्स द्वारा सोसाइटी से धान उठाने के बजाए स्थानीय दलालों को बेची गई। इन्होंने कागजों पर ट्रक से धान का फर्जी परिवहन दिखाया, जबकि न तो इन ट्रक का टोल कटा और न ही टोल कैमरे में दिखे।

जांच में मिली गड़बड़ी

जांच समिति ने यह गड़बड़ी पकड़ने के लिए धान का परिवहन करने वाले ट्रक का एनएचएआइ के टोल नाके से मूवमेंट की जांच की। परिवहन विभाग की सहायता से ट्रक की श्रेणी प्रकार और लोडिंग क्षमता की जांच में गड़बड़ी सामने आई और ट्रक यहां से गुजरे नहीं।

सांठगांठ आई सामने

जांच समिति ने जब पूरे फर्जीवाड़े के तार जोड़े तो कई अधिकारी, कर्मचारियों और मिलर्स की सांठगांठ सामने आई। इस दौरान 17 मिलर्स ने धान का परिवहन करने के बजाए उसे जबलपुर में ही बेच दिया। इसमें मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन के अधिकारी से लेकर ऑपरेटर और केंद्र प्रभारी व कंप्यूटर ऑपरेटर सीधे तौर पर शामिल रहे।

परिवहन का फर्जी रिकॉर्ड

18 में से 17 राइस मिलर संचालक ने पूरा परिवहन का फर्जी रिकॉर्ड तैयार किया। इसके साथ ही 25 सोसायटियों यानी उपार्जन केंद्र द्वारा राइस मिलर संचालक और मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन जबलपुर के कर्मचारियों के साथ मिलकर अन्य जिलों में धान बेचने का रिकार्ड तैयार कर उसे कागजों पर दिखाया गया।

571 ट्रक फर्जी धान दिखाई

17 मिलर ने यह फर्जीवाड़ा किया, इन्होंने टोल पर 571 ट्रक की फर्जी जानकारी दिखाई। धान ले जाने वाले जिन वाहनों का उपयोग किया गया, उन ट्रकों में कार के नंबर दिखाए गए। ऑनलाइन पोर्टल में 324 डीओ जारी हुए, जिसमें 14 हजार मीट्रिक टन धान थी। जांच टीम ने मोहतरा टोल, बहोरीपार टोल, सालीवाड़ा टोल और शहपुरा टोल की जांच की।

दलालों ने भी खेला खेल

जबलपुर की 25 सोसायटियों ने कम्प्यूटर ऑपरेटर के साथ मिलकर बड़ा खेल खेला। उन्होंने उपार्जन केंद्र के प्रभारी और उससे जुड़े वेयरहाउस संचालक के साथ मिलकर उपार्जन केंद्र ने जिस धान को आनलाइन पोर्टल पर चढ़ाया, लेकिन भौतिक तौर पर वह है ही नहीं। इनका फर्जी वाहन में परिवहन दिखाया। नागरिक खाद्य आपूर्ति निगम को जिन वाहनों के परिवहन की जानकारी भेजी गई, वह ट्रक की नहीं बल्कि कई कारों की थी। इतना ही नहीं फर्जीवाड़े में जबलपुर के दलाल भी शामिल रहे।

अग्रिम जमानत भी हो चुकी है खारिज

अनूपपुर के कृषि उपसंचालक निलंबित, 2.29 करोड़ रुपए के गबन पर गिरी गाज

अनूपपुर। जागत गांव हमार

अनूपपुर जिले में जैविक कृषि के लिए प्राप्त डीएमएफ की राशि में ढाई करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में कृषि विभाग ने अनूपपुर जिले में पदस्थ उपसंचालक कृषि एनडी गुप्ता को निलंबित कर दिया है। दो वर्षों से इस मामले की जांच पूरी हो चुकी थी। 11 फरवरी को तत्कालीन उपसंचालक कृषि एवं परियोजना संचालक नारायण दास गुप्ता के खिलाफ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और गबन के तहत केस दर्ज किया था। यह केस सरकारी राशि में 2 करोड़ 29 लाख से अधिक के गबन की पुष्टि के बाद दर्ज किया गया था। इसके बाद उपसंचालक कृषि अनूपपुर एनडी गुप्ता फरार चल रहे थे, जिस पर शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया है। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग मंत्रालय ने एनडी गुप्ता के विरुद्ध डीएमएफ से प्राप्त राशि के दुरुपयोग के कारण कलेक्टर अनूपपुर के अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव पर उन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया है। इसके बाद मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (क) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक, किसान कल्याण और कृषि विकास जबलपुर रहेगा। इस दौरान गुप्ता को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

जमानत याचिका खारिज | विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पंकज जायसवाल, अनूपपुर की न्यायालय ने हाल ही में उपसंचालक एनडी गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। अब उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा-उज्जैन को सांस्कृतिक राजधानी बनाएंगे

उज्जैन और शाजापुर के 100 गांव को मिलेगा भरपूर पानी

हर खेत-हर घर पहुंचेगा जल

भोपाल। जागत गांव हमार

नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत पाइप लाइन का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन जिले के तराना में लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने 9.64 करोड़ की लागत से बने इंदौख हाई लेवल ब्रिज का लोकार्पण, 7.15 करोड़ की लागत वाले उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का भूमिपूजन, 5.73 करोड़ की लागत वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण और 5.21 करोड़ की लागत की 11 नल-जल परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। 2489.65 करोड़ की इस परियोजना से उज्जैन जिले की दो तहसील (तराना, घटिया), विधानसभा क्षेत्र तराना के 83 गांवों की 27490 हेक्टेयर भूमि और शाजापुर जिले की एक तहसील (शाजापुर) विधानसभा क्षेत्र शाजापुर के 17 गांवों की 2728 हेक्टेयर जमीन का फायदा होगा। परियोजना से 100 गांवों की 30218 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। सीएम ने कहा कि मप्र को पार्वती-कालीसिंध-चंबल और केन-बेतवा लिंक परियोजनाओं की सौगात मिली है। हर खेत तक सिंचाई का पानी और हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचे, यह हमारी सरकार का संकल्प है। नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के लोकार्पण से नर्मदा की पावन धारा तराना की धरती तक पहुंच गई।

महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण

सीएम ने कहा कि प्रदेश में सबके जीवन की बेहतरी के लिए लगातार कार्य हो रहे हैं। महिलाओं की प्रगति के लिए सरकारी नौकरियों में उन्हें 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही, लाड़ली बहनों को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग में कार्यरत महिलाओं को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। युवाओं के लिए आने वाले एक वर्ष में एक लाख भर्तियां होंगी।

दूध पर 5 रुपए लीटर बोनस

सीएम ने कहा कि प्रदेश के किसानों को निरंतर सौगातें मिलती रहेंगी। किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त सरकार किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता दे रही है। साथ ही, किसानों से 2600 रुपए क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जा रहा है। हम दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी संकल्पित हैं। किसानों को दूध पर 5 रुपए लीटर प्रोत्साहन राशि प्रदान करेंगे।

26 मार्च से 1 अप्रैल तक लेंगे सामूहिक अवकाश

सात दिन छुट्टी पर रहेंगे 23000 पंचायत सचिव

भोपाल। मध्यप्रदेश के करीब 23 हजार पंचायत सचिव सात दिन के सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। वे 26 मार्च से 1 अप्रैल तक छुट्टी लेंगे। तीन से चार महीने का वेतन नहीं मिलने के चलते भी वे नाराज हैं और अब सड़क पर उतरेंगे। मध्यप्रदेश पंचायत सचिव संगठन के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया, 7 सूत्री मांगों को लेकर संगठन के 313 ब्लॉक और 52 जिला मुख्यालय के ब्लॉक- जिला अध्यक्ष कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपेंगे। इसमें बताया जाएगा कि 25 मार्च तक यदि मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो 26 मार्च से वे सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे।

इन मांगों को लेकर अवकाश पर जाएंगे

-हर महीने 1 तारीख को वेतन देने के आदेश जारी हो। अभी तीन से चार महीने तक वेतन नहीं मिल रहा है।

-मुख्यमंत्री की घोषणा और आदेश जारी होने के 20 महीने बाद भी समयमान वेतनमान का सचियों को लाभ नहीं मिल पाया है। यह तत्काल हो।

-हर महीने प्रदेश की 313 जनपद में से 50 में वेतन के लिए लाले होते हैं। इसलिए बजट में अलग से प्रावधान किया जाए।

-रोजाना छह हजार के गुलाब दूसरे शहरों में भेज रहे

पॉली हाउस बनाने में करीब 30 लाख रुपए खर्च किए

गुना के गुलाबों की दुबई और बांग्लादेश में डिमांड इंजीनियरिंग छोड़ किसान बना, बदल गई किस्मत

गुना। जागत गांव हमार

जागत गांव हमार अपने इस अंक में अपने पाठकों को एक ऐसे युवा किसान के बारे में बताने जा रहा है, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ नौकरी शुरू कर दी। इसी दौरान किसी दोस्त के पॉली हाउस पहुंच गए। दोस्त ने आइडिया दिया और उससे उनकी किस्मत बदल गई। यहीं से उनका रिश्ता मिट्टी से जुड़ गया। उनके पॉली हाउस में लगाए गए गुलाब की महक दुबई और बांग्लादेश तक पहुंच रही है। वे रोजाना 5-6 हजार रुपए के गुलाब जयपुर और दिल्ली भेज रहे हैं। रोज 60-70 बंडल फूलों का उत्पादन हो रहा है। पहले वे केवल गुलाबी कलर का गुलाब उगाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कई और रंगों के गुलाब उगाना शुरू किया है। इनमें ऑरेंज, पीला, सफेद गुलाब शामिल हैं। हम बात कर रहे हैं गुना शहर की कोकाटे कॉलोनी में रहने वाले 27 साल के इंजीनियर अनिमेश श्रीवास्तव की। उन्होंने भोपाल के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। अनिमेश ने बताया कि रोज करीब 60-70 बंडल गुलाब का उत्पादन होता है।

गुलाब की खेती की कहानी, किसान की जुबानी

मैंने पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग एंड टेक्नोलॉजी से 15 दिन की ट्रेनिंग ली। वहां मैंने किस किस्म की मिट्टी में कौन सी फसल बेहतर हो सकती है, यह सीखा। 2018 में गुना से 30 किमी दूर म्याना के पास अपनी जमीन पर खेती शुरू की। 3 एकड़ में पॉली हाउस बनाया और गुलाब की खेती शुरू की। पुणे के तलेगांव से डच रोज किस्म के पौधे मंगाए। देश में केवल यही एक ऐसी जगह है, जहां डच रोज के पौधे मिलते हैं। डच रोज का एक पौधा 11 रुपए में खरीदा। कुल तीन एकड़ में 24 हजार पौधे लगाए। 5 साल तक यह पौधे लगातार उत्पादन देते हैं। पॉली हाउस बनाने में करीब 30 लाख रुपए खर्च किए। इसमें सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिली। लगभग 12-13 लाख रुपए का निवेश किया। मेरे गुलाबों का सबसे बड़ा मार्केट दिल्ली और जयपुर है। इसकी वजह है कि गुना से यहां ट्रांसपोर्ट आसान है। रोजाना ट्रेन से जयपुर और दिल्ली गुलाब भेजे जाते हैं। दिल्ली के कुछ व्यापारी यहां से गुलाब खरीदकर दुबई और बांग्लादेश तक एक्सपोर्ट करते हैं।

एक एकड़ में लगाए जाते हैं 30 हजार पौधे

जागत गांव हमार को अनिमेश ने बताया कि पौधे रोपते समय एक-एक कर उचित दूरी (15 सेमी) पर लगाए जाते हैं। हमने गुलाब की डच रोज किस्म के पौधे विशेष रूप से पुणे के तलेगांव से मंगाए हैं। एक पौधे की कीमत 4-5 रुपए होती है और एक एकड़ में लगभग 30,000 पौधे लगाए जाते हैं। ये पौधे 5 वर्षों तक उत्पादन देते हैं और एक बार फूल तोड़ने के बाद 40 दिन में नए फूल खिल जाते हैं। पूरे पॉलीहाउस प्रोजेक्ट पर लगभग 55 लाख रुपए की लागत आई, जिसमें सरकार से सब्सिडी भी मिली।

सिंचाई और पोषण व्यवस्था

सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिसमें दो पाइप लगाए जाते हैं। एक पाइप से पौधों की जड़ों को पानी दिया जाता है और दूसरे पाइप से पत्तियों और टहनियों को सिंचित किया जाता है। पॉलीहाउस के बाहर एक पानी का टैंक बनाया जाता है, जिससे पानी की आपूर्ति की जाती है। पानी की मात्रा संतुलित रखनी होती है क्योंकि ज्यादा पानी से बेड टूट सकते हैं और कम पानी से पौधे सूख सकते हैं। रोजाना फर्टिगेशन प्रक्रिया के तहत कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम और एनपीके का छिड़काव किया जाता है, जिससे पौधों को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं और उनका विकास सही ढंग से होता है।

पहली कली को तोड़ देना चाहिए

एक महीने के बाद गुलाब का पौधा बढ़ता है और मदर शूट से कलियां निकलती हैं। मदर शूट मतलब मुख्य शाखा है। उसमें से जो सबसे पहले कलियां निकलती हैं, उन्हें काट देते हैं, ताकि तना और अधिक मोटा हो जाए। यह कली दिखने के बाद सबसे पहले काटनी चाहिए। इस कली को तोड़ने के बाद 2-3 आंखें मुख्य शाखा पर बढ़ती हैं। यही बाद में शाखाओं में तब्दील हो जाती हैं। इन शाखाओं में कलियां विकसित हो जाती हैं। जब पौधा विकास की इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो मदर शूट को पथ की दिशा की ओर झुकना किया जाता है। कुछ ही दिनों में मदर शूट के झुकने के बाद गुलाब का पौधा अंकुरित हो सकता है। इनका उपयोग पौधे की संरचना के लिए किया जाता है। संरचना जितनी अच्छी होगी, पौधे की पैदावार उतनी ही अधिक होगी। काम कुशल व अनुभवी मजदूरों से कराते हैं।

ऐसे करें देखभाल

गुलाब के पौधे में झुकाव करना

पेड़ पर अनावश्यक पत्तों की भीड़ से बचने के साथ-साथ पेड़ पर पर्याप्त मात्रा में पते बनाए रखने के लिए गुलाब में झुकना मतलब पौधे को आड़ा कर देते हैं। यह स्वस्थ शाखाओं के विकास को बढ़ावा देता है। यह रोगों और कीटों को नियंत्रित करने में मदद करता है। झुकने से पहले शाखाओं की कलियों को हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत शाखा को बढ़ने दिया जाता है। यदि अंकुर कमजोर होते हैं, तो उन्हें फिर से मोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनका उपयोग उत्पादन के लिए नहीं किया जाता है। अधिक गुणवत्ता वाले फूल प्राप्त करने के लिए डिस्बडिंग किया जाता है। डिस्बडिंग का मतलब है कि अन्य कलियां जो गुलाब की पंखुड़ियों के ठंठल पर उगती हैं, उन्हें हटाना होता है। प्राथमिक कलियां हैं, वे हटा दी जाती हैं। इससे पौधे को बिना ऊर्जा बर्बाद किए अधिक गुणवत्ता वाले फूल मिलते हैं। ऑफ सीजन (जून-जुलाई) में गुलाबों की छंटाई की जाती है, इसे काटते नहीं हैं। काटने से गुलाब की नई शाखाएं कमजोर हो जाती हैं। दो पत्तियों पर छंटाई की जाती है और रोगग्रस्त शाखाओं को हटा दिया जाता है।

स्केल कीट रोग से बचाव का तरीका

अनिमेश ने बताया कि यह रोग पौधों के लिए अधिक हानिकारक होता है। स्केल किट रोग एक पतले सफेद आवरण के पीछे खुद को छिपाए रखता है। यह पौधे के विकास को रोक देता है। ऐसे रोग पौधे की कोमल तने का रस चूसकर उसे खत्म कर देता है, जिससे पौधा पूरी तरह से सूख जाता है। इस तरह के रोग से रोकथाम के लिए क्लोरोपायरीफॉस 2 प्रतिशत के 10 किलो पैक्ट एक एकड़ में इस रोग से ग्रसित पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। इस रोग का अधिक प्रभाव होने पर बुप्रोफेजिन 25 एससी के 30 मिलिलीटर को 15 लीटर पानी में मिलाकर अच्छे से छिड़काव करना चाहिए।

मिलिबग कीट रोग से ऐसे करें बचाव

यह कीट रोग पौधों की कोमल डुंख और पत्ते की निचली सतह से रस को चूस कर पौधों को अधिक नुकसान पहुंचाता है, जिससे पौधा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इस रोग की रोकथाम के लिए बुप्रोफेजिन 25 एससी का उचित मात्रा में छिड़काव करना चाहिए। गुलाब के लिए सबसे अच्छी खाद गर्मियों में गुलाब के पौधे के लिए गोबर की खाद सबसे अच्छी खाद मानी जाती हैं, क्योंकि यह खाद आसानी से उपलब्ध है। इसमें गुलाब के पौधे के विकास के लिए सभी जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे- नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस आदि।

राज्य स्तर पर सम्मानित हो चुके गुलाब किसान

गुना में गुलाब उगाने वाले किसान राज्य स्तर पर भी सम्मानित हो चुके हैं। 11 और 12 जनवरी को भोपाल के गुलाब उद्यान में 44वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में पूरे भारत से गुलाब के लगभग 700 उत्कृष्ट नमूने प्रस्तुत किए गए। गुना जिले की किसान लता अग्रवाल निवासी ग्राम मावन और इंदु जादौन निवासी हनुमान टेकरी के पास गुना ने अपने पॉली हाउस में उगाए गए गुलाब के डच रोज कट फ्लावर प्रदर्शनी में भेजकर जिले का गौरव बढ़ाया। लता अग्रवाल को व्यवसायिक पुष्प उत्पादकों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। वहीं इंदु जादौन को उसी श्रेणी में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

गुलाब के खेती की मिट्टी की निराई करना जरूरी

अनिमेश के अनुसार, सिंचाई के कारण क्यारी की सतह सख्त हो जाती है और पौधे की जड़ों को खाद और हवा मिलना मुश्किल हो जाता है। इस कारण क्यारी पर मिट्टी को अधिक नहीं दबाना चाहिए। क्यारी की मिट्टी में हर 15 दिन में निराई-गुड़ाई की जाती है। मिट्टी की परत खुरचने तक क्यारी पर 5 सेमी गहरी निराई से जड़ों के टूटने की आशंका अधिक होती है। गुलाब के पौधों और फूल दोनों में रोग लग जाते हैं, इसलिए इन्हें अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। गुलाब में सुंडियां, खैरा रोग, उल्टा सूखा जैसे रोग लगते हैं। इसके अलावा कीट रोग भी पौधों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। यह रोग पौधों और फूलों दोनों पर ही देखने को मिलते हैं। इस तरह के रोग लग जाने पर पौधे की शाखाएं सूखने लगती हैं साथ ही फूल और नई कलियां भी सूख जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए पांच ग्राम टैंगक्सोन नाम के पाउडर 6 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। सफेद मक्खी का रोग गुलाब के पौधों में सबसे ज्यादा लगता है। इस रोग में सफेद मक्खियां पौधों की पत्तियों का रस चूस लेती हैं। इससे पत्तियां नष्ट होकर गिर जाती हैं। इस रोग से रोकथाम के लिए डायफेनथ्रीयुरोन 50 डब्ल्यूपी के 20 ग्राम पाउच को लगभग 15 लीटर पानी में अच्छे से मिलाकर पौधों में छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ ही स्पाइरोमेसिफेन 240 स्ष्ट की 20 मिलीलीटर की मात्रा को 18 से 20 लीटर पानी में छिड़काव करना चाहिए।

सब्सिडी का खेलः भूमिहीन, मृत और जो गांव में ही नहीं, उन्हें भी कागजों में दे दिया कनेक्शन

किसानों के नाम पर फर्जी कनेक्शन का खेला

» नौकरी बचाने फर्जीवाड़ाः सब्सिडी से लाइनलॉस -बिजली चोरी का अंतर पाटते अफसर

» टीकमगढ़ः पैस लेने के बाद रसीद नहीं देते, दो गांव में 98 पंप कनेक्शन, एक सही नहीं

-हर किसान के नाम पर हर माह 5828 रु. की सब्सिडी हड़प रही बिजली कंपनी

-16 जिलों में 3.22 लाख पंप कनेक्शन से हर माह 190 करोड़ की सब्सिडी ले रही

भोपाल। जागत गांवह मार

मध्यप्रदेश के विदिशा जिले के कांकलखेड़ी गांव के सुरेंद्र के पिता नारायण अहिरवार के पास एक एकड़ जमीन है। इनका नाम अटल कृषि ज्योति योजना में है। इस योजना के तहत उन्हें सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलती है, जिससे बिजली कंपनी हर महीने सरकार से 5,828 रुपए की सब्सिडी ले रही है। लेकिन सुरेंद्र का कहना है कि उनके पास न तो 5 एचपी की मोटर है, न ही पंप कनेक्शन। यह सिर्फ एक मामला नहीं है, बल्कि कई अन्य जिलों में भी ऐसी ही स्थिति है। खास बात यह है कि इनमें से कुछ कनेक्शन मृत लोगों के नाम है। कुछ गांव में नहीं हैं, लेकिन उनके भी नाम योजना में शामिल किए गए हैं। बिजली कंपनी के अफसरों ने एससी-एसटी किसानों के नाम पर फर्जी कनेक्शन दिखाकर सरकार से सब्सिडी हड़पने का काम किया है। सरकार इस योजना में एससी-एसटी के एक हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को मुफ्त बिजली देती है, लेकिन जब जांच की गई तो इन किसानों के नाम पर पंप कनेक्शन फर्जी थे। विदिशा, भिंड, सागर समेत प्रदेश के 16 जिलों में एससी-एसटी किसानों को योजना के तहत 3,22,661 पंप कनेक्शन बांटे गए हैं। इनसे बिजली कंपनी को हर महीने 190 करोड़ रुपए सब्सिडी मिल रही है।

16 जिलों में 322661 पंप कनेक्शन

जिला	कनेक्शन	सब्सिडी राशि
नर्मदापुरम	93112	54.34 करोड़
शिवपुरी	66700	48.42 करोड़
दतिया	31814	21 करोड़
सागर	35057	18.57 करोड़
हरदा	3516	1.44 करोड़
राजगढ़	28535	15.77 करोड़
रायसेन	16798	9.22 करोड़
बैतूल	12789	7.01 करोड़
विदिशा	12605	3.98 करोड़
गुना	4104	2.25 करोड़
श्योपुर	3229	1.82 करोड़
टीकमगढ़	3498	1.79 करोड़
अशोकनगर	2152	1.52 करोड़
दमोह	7766	4.29 करोड़
भिंड	271	14.77 लाख
मुरैना	715	39.34 लाख
कुल	**322661**	**190.44 करोड़**

भूमिहीन, मृत और जो गांव में ही नहीं...

टीकमगढ़ के बड़ागांव के पजना अहिरवार ने बताया मेरी डेढ़ एकड़ जमीन है। अर्थ-फेस की मोटर है। 5 हॉर्स पावर की मोटर नहीं है। अधिकारी 6 हजार रु मांगते हैं, मैं 4-5 हजार रु बिजली दफ्तर जाकर दे आता हूं। वे रसीद कभी नहीं देते। टीकमगढ़ के बड़ागांव में 33 पंप कनेक्शन हैं। इनमें से 32 के नाम पर 5 एचपी की मोटर और एक के नाम पर 3 एचपी की मोटर दर्ज है। सूची के 30 आईवीआरएस नंबर से किसानों के नाम सर्च नहीं हो रहे। ये कनेक्शन फर्जी तरीके से जोड़े गए। एक किसान गांव में नहीं रहता। एक की मौत हो चुकी और एक के पास सिंगल फेस की मोटर है। टीकमगढ़ के दिगौड़ा में 65 पंप कनेक्शन हैं। इनमें से 23 के नाम आईवीआरएस नंबर से सर्च ही नहीं हो रहे, जो फर्जी हैं। एक की मौत हो चुकी। चैनपुरा मोहल्ला के बैजनाथ निराला ने बताया बिजली कंपनी की सूची में जो नाम हैं उन्हें कभी नहीं देखा। भूंकर जाति के लोग यहां नहीं रहते। मैं यहां से जनपद का चुनाव लड़ा हूं। मुझे इलाके के सभी लोगों की जानकारी है।

फर्जी नाम जोड़कर पंप कनेक्शन दिए

बिजली कंपनी के अधिकारी एससी-एसटी फ्री बिजली योजना में फर्जी नाम जोड़कर 5 एचपी का पंप कनेक्शन दर्शाते हैं, ताकि प्रदेश सरकार से सब्सिडी मिलती रहे। असल में, दावा किए गए पंप कभी चले ही नहीं। इससे खपत ही नहीं हुई। लेकिन सब्सिडी कंपनी के खाते में जाती है। यह राशि अधिकारियों द्वारा लाइनलॉस और बिजली चोरी की भरपाई में इस्तेमाल होती है। सब्सिडी से अधिकारियों के वेतन की कटौती रोकने और चोरी को छिपाने में मदद मिलती है, जिससे लाइनलॉस 25-30 से घटकर 10-15 प्रतिशत रह जाता है।

योजना में फ्री बिजली

इस योजना में एससी-एसटी के किसानों को सिंचाई करने 5 हॉर्स पावर तक की मोटर के लिए फ्री बिजली दी जाती है। इसके एवज में सरकार बिजली कंपनियों को पैसा देती है। एक हेक्टयर तक के एससी-एसटी के किसानों को बिल के नाम पर कोई पैसा नहीं देना पड़ता।

2 गांव में 58 पंप कनेक्शन

कुड़ारी गांव के जय अहिरवार ने बताया कि पिता मूलचंद की 2023 में मृत्यु हो गई। मेरी जमीन परती पड़ी है और 5 एचपी की मोटर नहीं है। जबकि बिजली कंपनी मूलचंद के नाम 5 एचपी का पंप कनेक्शन दर्शाकर सरकार से सब्सिडी ले रहे हैं।

कुड़ारी में 31 कनेक्शन

कुड़ारी गांव में कंपनी ने 31 पंप कनेक्शन। जबकि यह सब फर्जी हैं। इनमें 5 किसानों की मौत हो चुकी है। 26 के पास जमीन ही नहीं है या वे गांव में नहीं रहते। इसी तरह सिलेरा में 27 पंप कनेक्शन 13 के पास जमीन नहीं या वे गांव में नहीं रहते। 1 की मौत हो चुकी है। 7 के पास अर्थ-फेस, 2 के पास 2 एचपी मोटर है। कंपनी ने सभी के नाम पर 5 एचपी मोटर दर्ज कर रखे हैं।

इधर, आयोग ने मांगा जवाब

इधर, विदिशा एवं प्रदेश के अन्य जिलों में अटल कृषि ज्योति योजना के तहत किसानों को मिलने वाली मुफ्त बिजली में भूमिहीन, मृत और जो गांव में ही नहीं है उन्हें भी सब्सिडी के लिए कागजों में बिजली कंपनी द्वारा कनेक्शन देकर हर महीने सरकार से 5000 रुपए से ज्यादा राशि की सब्सिडी लेने का मामला सामने आया है। जो किसानों की जमीन ही नहीं है, और जो मृत हो गए हं या जो गांव में ही नहीं है, उन्हे भी योजना में शामिल करके उनके नाम से भी बिजली कंपनी द्वारा उनके नाम से सब्सिडी ले रही है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल से मामले की जांच कराकर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन एक माह में मांगा है।

हम दो-तीन जिलों की जांच कराकर सर्वे कराएंगे। यह सही है, सभी के पास 5 एचपी की मोटर नहीं हो सकती। सही है, कंपनियां यह लॉस सब्सिडी से छिपा लेती हैं। जांच कराएंगे।
नीरज मंडलोई, एसीएस, ऊर्जा विभाग

सरकार का दावा-खर्च कम और मुनाफा ज्यादा

गाय की देसी पांच नस्लें किसानों को बना देंगी धनवान

भोपाल। जागत गांव हमार

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेती-किसानी के बाद पशुपालन के बिजनेस को आमदनी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। उसमें भी गौ पालन किसानों और पशुपालकों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। गाय से ना सिर्फ दूध, बल्कि खेती के लिए गोबर भी मिलता है जो कि खाद के काम आता है और इसके इस्तेमाल से खेती की लागत में भी कमी आती है, जिस वजह से गाय पालन की ओर हर वर्ग के किसानों का रुझान काफी तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप गाय की अधिक दूध देने वाली देसी नस्ल की तलाश में हैं तो आप इन पांच गाय का पालन कर सकते हैं। ये गायें अन्य देसी गायों की तुलना में काफी अधिक मात्रा में दूध देती हैं।

गाय की पांच देसी नस्ल

1-सिरोही नस्लः सिरोही गाय की पहचान ये है कि इसकी ऊंचाई लगभग 120 सेमी तक होती है। वहीं, इस नस्ल की गाय अधिकांश सफेद या भूरा-सफेद रंग की होती है। इस गाय की विशेषता ये है कि ये एक ब्यांत में औसतन 1600 लीटर तक दूध देती है। इस गाय के दूध में 4.64 प्रतिशत फैट पाया जाता है। वहीं ये गाय प्रतिदिन लगभग 10 से 12 लीटर दूध देती है।

2-मेवाती नस्लः अगर आप गौ पालन करना चाहते हैं तो मेवाती गाय की नस्ल को पाल सकते हैं। इस गाय की पहचान ये है कि ये आमतौर पर सफेद रंग की होती है। इनकी ऊंचाई 125 सेमी होती है। सींग आकार में छोटे से मध्यम होते हैं। इसके अलावा चेहरा लंबा, माथा सीधा, कभी-कभी थोड़ा उभरा हुआ होता है। साथ ही इस गाय के थन पूरी तरह विकसित होते हैं। वहीं, इस गाय की विशेषता ये है कि ये एक ब्यांत में औसतन 900 से 1000 लीटर दूध देती है। इसके अलावा इस नस्ल की गाय प्रतिदिन लगभग 5 से 7 लीटर दूध देती हैं।

3-थारपारकर नस्लः गाय की देसी नस्ल थारपारकर भारत की सर्वश्रेष्ठ दुधारू गायों में गिनी जाती है। थारपारकर का नाम इसके उत्पत्ति स्थल यानी थार रेगिस्तान से लिया गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मुताबिक थारपारकर नस्ल की गाय औसतन एक ब्यांत में 1700 लीटर तक दूध देती है। वहीं, इस नस्ल की गाय हर रोज 12 से 16 लीटर तक दूध देती है।

4-राठी नस्लः देशी नस्ल के गायों में राठी नस्ल की गाय काफी दुधारू नस्ल मानी जाती है। इस नस्ल की खासियत ये है कि ये देश के किसी भी क्षेत्र में रह लेती है। राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। वहीं, राठी नस्ल की गाय प्रतिदिन लगभग 7 से 12 लीटर तक दूध देती है, जबकि, अच्छी देखभाल और खानपान होने पर 18 लीटर तक भी दूध दे सकती है।

5-लाल कंधारी नस्लः लाल कंधारी नस्ल छोटे किसानों के लिए बहुत लाभकारी गाय है, क्योंकि इसकी देखभाल में ज्यादा लागत नहीं आती है और इसे खिलाने के लिए हमेशा हरे चारे की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ऐसा मानते हैं कि गाय की इस नस्ल को चौथी सदी में कांधार के राजाओं द्वारा विकसित किया गया था। इसे लखाल्बुन्दा भी कहा जाता है। वहीं, लाल कंधारी गाय प्रतिदिन 4 से 6 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है।

भारतीय श्री अन्न (मिलेट्स) बाजरा : उत्पादन एवंपोषण सुरक्षा

» डॉ. शालिनी चक्रवर्ती
– प्रधान वैज्ञानिक
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद – कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, मप्र

श्री अन्न एक प्रकार का अनाज है जो विश्व के कई भागों विशेषत: अफ्रीका एवं एशिया में लोकप्रिय है। यह विश्व के कई हिस्सों विशेष रूप से अफ्रीका एवं एशिया का मूल भोजन है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अनुसार, अनुमानित 1.2 बिलियन आबादी अपने आहार के रूप में श्री अन्न का सेवन करते हैं। वर्ष 2020 में 28 मिलियन मीट्रिक टन के अनुमानित उत्पादन के साथ पिछले कुछ वर्षों में श्री अन्न उत्पादन अपेक्षाकृत स्थिर रहा है। श्री अन्न (मिलेट्स) का अधिकांश उत्पादन अफ्रीका में होता है, जिसके बाद एशिया का स्थान आता है। भारत श्री अन्न (मिलेट्स) का सबसे बड़ा उत्पादक है।

भारत के बाद नाइजर तथा चीन का स्थान आता है। अन्य प्रमुख श्री अन्न (मिलेट्स)-उत्पादक देशों में बुर्किना फासो, माली और सेनेगल शामिल हैं। चूंकि विकसित देशों में श्री अन्न (मिलेट्स) एक प्रमुख खाद्य फसल नहीं है, यह विकासशील देशों में कई लोगों के आहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय श्री अन्न (मिलेट्स) पौष्टिकता से भरपूर समृद्ध, सूखा सहिष्णु फसल है जो ज्यादातर भारत के शुष्क एवं अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है। यह एक छोटे बीज वाली घास के प्रकार का होता है जो वनस्पति प्रजाति (Poaceae) से संबंधित हैं। यह लाखों संसाधन रहित गरीब किसानों के लिए खाद्य एवं पशु-चारे का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं तथा भारत की पारिस्थितिक और आर्थिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस श्री अन्न (मिलेट्स) को मोटा अनाज या गरीबों के अनाज के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय श्री अन्न (मिलेट्स) पौष्टिकता से भरपूर गेहूं और चावल से बेहतर है क्योंकि यह प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं। यह ग्लूटेन-मुक्त भी होते हैं और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स निम्न होता है, जो इन्हें सीलिएक डिज़ीज़ या मधुमेह रोगियों के लिए अनुकूल बनाता है। इन कारणों से, श्री अन्न (मिलेट्स) आने वाले वर्षों में एक महत्वपूर्ण खाद्य फसल बना रहेगा।

भारत में हाल के वर्षों में श्री अन्न (मिलेट्स) का उत्पादन बढ़ रहा है। भारत श्री अन्न (मिलेट्स) के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और भारतीय किसान सूखा प्रतिरोधी फसल के रूप में इसकी खेती तेजी से कर रहे हैं। भारत सरकार भी अपने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के भाग के रूप में श्री अन्न (मिलेट्स) के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इन कारकों के परिणामस्वरूप, भारत में आने वाले वर्षों में श्री अन्न (मिलेट्स) के उत्पादन में वृद्धि जारी रहने की आशा की गई है। भारत विश्व में श्री अन्न (मिलेट्स) के शीर्ष 5 निर्यातकों में से एक है। श्री अन्न (मिलेट्स) का विश्व निर्यात 2020 में 400 मिलियन डॉलर से बढ़कर 470 मिलियन डॉलर हो गया है। भारत ने 2021-22 में 62.95 मिलियन डॉलर के मुकाबले वर्ष 2022-23 में 75.46 मिलियन डॉलर मूल्य के श्री अन्न (मिलेट्स) का निर्यात किया।

भारतीय श्री अन्न (मिलेट्स) उत्पादक राज्य: भारत श्री अन्न (मिलेट्स) के प्रमुख उत्पादकों एवं आपूर्तिकर्ताओं में से एक है, और देश में कई श्री अन्न (मिलेट्स) स्रोत बिंदु स्थित हैं। भारत में मुख्य श्री अन्न (मिलेट्स) उगाने वाले राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं, इन राज्यों में बड़ी संख्या में श्री अन्न (मिलेट्स) किसान हैं जो घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए अनाज उगाते हैं। **श्री अन्न बाजरा:** सबसे व्यापक रूप से खेती किया जाने वाला श्री अन्न (मिलेट्स) बाजरा है। बड़े तने, पत्ते और शीर्ष भाग ग्रीष्मकालीन अनाज घास की विशेषता है। कृषि भूमि एवं अफ्रीका और एशिया के कुछ भागों में जो केवल सीमित मात्रा में अन्य फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, खाद्य सुरक्षा में योगदान के संदर्भ में, बाजरा श्री अन्न की सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है। ज्वार या मक्का जैसे अन्य श्री अन्न की तुलना में, यह नमी को अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित करता है, संघनित पुष्पगुच्छ जिसकी लंबाई 10 से 150 सेमी होती है, इस अनाज को उगने में सहारा देती है। गर्मी और सूखे की स्थिति में, बाजरा में सभी श्री अन्न (मिलेट्स) की तुलना में सबसे अधिक उपज क्षमता होती है। वजन घटाने की प्रक्रिया में बाजरा काफी फायदेमंद हो सकता है।

भारत में बाजरा का उत्पादन: बाजरा एक लचीला, छोटे बीज वाली घास है जो चारे और मानव उपभोग के लिए उगाई जाने वाली अनाज या अनाज का समूह है। बाजरा कई तरह की पारिस्थितिक स्थितियों के अनुकूल होता है और वर्षा आधारित और शुष्क जलवायु में अच्छी तरह से पनपता है। बाजरे के ये गुण उन्हें कृषि की दृष्टि से अन्य वाणिज्यिक फसलों से बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा, बाजरे में सूक्ष्म पोषक तत्व और बायोएक्टिव फ्लेवोनोइड्स के कारण अन्य अनाजों की तुलना में पोषण संबंधी श्रेष्ठता होती है, जो उन्हें अत्यधिक मूल्यवान बनाता है। इन अनाजों में उच्च प्रोटीन सामग्री उन्हें शाकाहारी और शाकाहारी आबादी के लिए आदर्श बनाती है, जो मुख्य रूप से अमेरिका, यूरोप और एशिया प्रशांत में स्थित है। बाजरा (मोती बाजरा और कम बाजरा) दुनिया भर के 93 से अधिक देशों में उगाया जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक देश है और इसकी खेती मुख्य रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और कनाज्टक में की जाती है। बाजरा ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड की आबादी के आहार का अभिन्न अंग रहा है।

खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए बाजरा: देश भर में स्वदेशी समुदायों द्वारा पारंपरिक रूप से खाए जाने वाले मोटे अनाज बाजरा आदिवासी समुदायों का मुख्य आहार थे। 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति ने देश में खाद्यान्न की कमी को सफलतापूर्वक पूरा किया, लेकिन इसने इन पारंपरिक अनाजों की जगह चावल और गेहूं को भी शामिल कर लिया। अपने पोषण मूल्य और जलवायु लचीलेपन के बावजूद बाजरे को गरीबों का अनाज माना जाने लगा। जबकि शहरी भारतीयों के बीच बाजरा की खपत धीरे-धीरे लोकप्रिय हो रही है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार, देशभर के ग्रामीण इलाकों में लगभग 68.3 फीसदी बच्चे (5 साल तक) और लगभग 58.5 फीसदी महिलाएं (15 से 49 साल) एनीमिया से पीड़ित पाई गईं, जो NFHS-y से दोनों समूहों में एनीमिया में 9.7फीसदी और 5.4फीसदी की वृद्धि दर्शाता है। बाजरा फाइबर, कैल्शियम और आयरन जैसे खनिजों से भरपूर होता है और अमीनो एसिड का एक अच्छा स्रोत है जो पोषण के लिए ज़रूरी है। पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए, महिला एवं बाल कल्याण विभाग अब गभज्वती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और छह साल से कम उम्र के उनके बच्चों के लिए आंगनवाड़ियों (ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र) में गर्म-पका हुआ भोजन और घर ले जाने वाले राशन सहित विभिन्न रूपों में बाजरे के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है, पोषण अभियान 2.0 के हिस्से के रूप में, एक सरकारी योजना जो आहार विविधता, खाद्य सुदृढ़ीकरण और बाजरे के उपयोग को लोकप्रिय बनाने पर केंद्रित है।

मूल्यवर्धित उत्पाद: बाजरा में पोषण की मात्रा बहुत अधिक होती है। वे विटामिन बी, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक से भरपूर होते हैं, और ग्लूटेन-मुक्त भी होते हैं और उनका जीआई (ग्लाइसेमिक इंडेक्स) कम होता है। इस प्रकार, बाजरा उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिन्हें गेहूँ से एलर्जी या असहिष्णुता है। बाजरे को उचित प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है ताकि उन्हें पचने योग्य उत्पादों में परिवर्तित किया जा सके। कुछ आम तौर पर खाए जाने वाले पौष्टिक उत्पाद इस प्रकार हैं: बाजरा रोटी, बाजरा लड्डू, बाजरा दलिया, बाजरा स्नैक्स।

बाजरे के उपभोग की परंपरा को पुनर्जीवित करने के प्रयास में, भारत सरकार के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया।केंद्र सरकार ने श्री अन्न योजना की शुरुआत देश में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से किया। इस योजना के तहत सरकार किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए आथिज्क और कृषि संबंधित मदद देगी। श्री अन्न (मिलेट्स) पारिस्थितिक परिस्थितियों की एक व्यापक श्रृंखला के लिए अत्यधिक अनुकूल है तथा यह फसल वर्षा-सिंचित क्षेत्र में अच्छी तरह से पनपता है। इस फसल को शुष्क जलवायु और पानी, उर्वरकों और कीटनाशकों की न्यूनतम आवश्यकता होती है।श्री अन्न (मिलेट्स) की खेती कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सहायता प्रदान करती है।

पशु बीमा: पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जरूरी

» डॉ. शिवम सिंह मेहरोत्रा
– पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मध्यप्रदेश शासन

आज के समय में पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय बन चुका है, जो किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन-यापन का मुख्य स्रोत है। पशुओं का पालन न केवल एक आर्थिक आवश्यकता है, बल्कि कृषि कार्यों में भी इनकी अहम भूमिका होती है। हालांकि, किसी भी व्यवसाय की तरह, पशुपालन में भी कई जोखिम होते हैं, जैसे कि पशु की बीमारी, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाएं। इन जोखिमों से बचने के लिए, पशु बीमा एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी उपकरण साबित हो सकता है।

पशु बीमा, खासतौर पर किसानों और पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।

पशु बीमा के फायदे: आर्थिक सुरक्षा: पशु बीमा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह पशु की मृत्यु, दुर्घटना या बीमारी की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। यदि बीमित पशु की कोई अप्रत्याशित घटना होती है, तो बीमा कंपनी उसके मूल्य का कुछ हिस्सा या पूरी राशि का भुगतान करती है। इससे किसान या पशुपालक को आर्थिक नुकसान से बचने में मदद मिलती है।

पशु की बीमारी और दुर्घटना से बचाव: जैसे इंसान के इलाज का खर्चा बढ़ सकता है, वैसे ही पशुओं की बीमारी और दुर्घटना के इलाज में भी काफी खर्चा आता है। पशु बीमा के तहत, पशु की बीमारी या दुर्घटना के इलाज का खर्च बीमा कंपनी उठाती है। इससे पशुपालकों को इलाज के खर्च को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती।

ऋण की सुविधा: पशु बीमा होने से किसानों और पशुपालकों को बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने में आसानी होती है। बीमित पशु को संपत्ति के रूप में रखा जा सकता है, जिससे ऋण लेने में सहूलियत होती है। यह ऋण उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने और सुधारने में मदद करता है।

वित्तीय जोखिम से सुरक्षा: प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़, तूफान, भूकंप आदि के कारण पशुओं की मृत्यु हो सकती है। ऐसे में, पशु बीमा इन आपदाओं से उत्पन्न होने वाले वित्तीय संकट को कम करता है। बीमा के तहत, प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई की जाती है, जिससे पशुपालक को अधिक नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता।

मनोबल में वृद्धि: जब पशुपालकों को यह विश्वास होता है कि उनके पास बीमा कवरेज है, तो उनका मनोबल ऊंचा रहता है। वे बिना किसी चिंता के अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उनके व्यापार में उतार-चढ़ाव के बावजूद, उनके पास एक वित्तीय सुरक्षा जाल होता है। पशु बीमा की प्रक्रिया- पशु बीमा की प्रक्रिया सरल और स्पष्ट होती है। इसे पाने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है:

बीमा कंपनी का चयन: सबसे पहले, पशुपालक को एक उपयुक्त बीमा कंपनी का चयन करना होता है। भारत में कई बीमा कंपनियां, जैसे एलआईसी, आइसीआईसीआई लॉम्बार्ड, बजाज एलियांज, आदि, पशु बीमा की पेशकश करती हैं। प्रत्येक कंपनी के पास विभिन्न योजनाएं और शर्तें होती हैं, इसलिए एक अच्छे विकल्प का चुनाव करना महत्वपूर्ण है।

बीमा पॉलिसी का चयन: पशुपालक को अपनी आवश्यकताओं के आधार पर बीमा पॉलिसी का चयन करना होता है। आमतौर पर, बीमा पॉलिसी पशु की उम्र, प्रजाति, और स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर निधार्रित की जाती है। कुछ पॉलिसी पूरी तरह से बीमारी और दुर्घटना को कवर करती हैं, जबकि कुछ पॉलिसी केवल प्राकृतिक आपदाओं या दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान को कवर करती हैं।

बीमा प्रीमियम का भुगतान: पशु बीमा लेने के बाद, पशुपालक को निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करना होता है। यह प्रीमियम मासिक, वार्षिक या अन्य किसी अवधि के अनुसार हो सकता है। प्रीमियम की राशि पॉलिसी के प्रकार और बीमित पशु की कीमत पर निर्भर करती है।

पशु की स्वास्थ्य जांच और मूल्यांकन: बीमा प्राप्त करने के लिए बीमा कंपनी आमतौर पर पशु की स्वास्थ्य जांच और मूल्यांकन करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि पशु स्वस्थ है और किसी प्रकार की बीमारियों का शिकार नहीं है। इसके बाद बीमा पॉलिसी जारी की जाती है।

बीमा पॉलिसी का दस्तावेजीकरण: बीमा कंपनी द्वारा बीमा पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जाता है, जिसमें सभी शर्तों और लाभों का उल्लेख होता है। यह दस्तावेज़ पशुपालक को सौंपा जाता है, जो इसे सुरक्षित रखता है।

दावा करने की प्रक्रिया: यदि बीमित पशु किसी कारणवश मर जाता है या बीमार हो जाता है, तो पशुपालक को बीमा कंपनी में दावा करना होता है। इसके लिए, पशुपालक को उचित दस्तावेज और चिकित्सा रिपोटज पेश करनी होती है। कंपनी के द्वारा किए गए मूल्यांकन के बाद, बीमा राशि का भुगतान किया जाता है।

पशु बीमा किसानों और पशुपालकों के लिए एक महत्वपूणज वित्तीय सुरक्षा उपकरण है। यह उन्हें पशुपालन से संबंधित किसी भी अप्रत्याशित घटना से होने वाले आथिज्क नुकसान से बचाता है। पशु बीमा से न केवल पशुपालकों को मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह उनके व्यवसाय की स्थिरता को भी सुनिश्चित करता है। हालांकि, सही बीमा योजना का चयन और बीमा की प्रक्रिया को समझना अत्यंत महत्वपूणज है, ताकि आप अपने पशु के लिए सही बीमा कवर प्राप्त कर सकें और किसी भी संकट के समय वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें।

भारत के प्रमुख जलाशयों में गिरता जलस्तर, चिंता जरूरी

भारत के प्रमुख जलाशयों का जल स्तर उनकी कुल क्षमता के 45 फीसदी तक गिर गया है। चिंता की बात है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मार्च से मई के बीच भीषण गर्मी वाले दिनों की संख्या सामान्य से अधिक रहने की भविष्यवाणी की है, जबकि दक्षिण-पश्चिम मानसून के आने में अभी भी दो महीनों का समय बाकी है। इस दौरान लू का कहर भी जारी रह सकता है। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने 20 माचज 2025 को इस बारे में जो आंकड़ों साझा किए हैं, उनके मुताबिक 155 प्रमुख जलाशयों में 8,070 करोड़ क्यूबिक मीटर (बीसीएम) पानी मौजूद है। वहीं इन जलाशयों की कुल क्षमता 18,080 करोड़ क्यूबिक मीटर है। मतलब कि इन जलाशयों में अपनी क्षमता का करीब 45 फीसदी पानी मौजूद है। पिछले वर्ष इसी अवधि के तुलना में जिन राज्यों के जलाशयों में इस समय कम पानी मौजूद है उनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड, ओडिशा, नागालैंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड शामिल हैं। चिंता की बात है कि उत्तरी क्षेत्र में जलाशयों का जल स्तर उनकी कुल क्षमता का महज 25 फीसदी रह गया है। इस क्षेत्र में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में 11 जलाशय हैं। हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों में जल भंडारण सामान्य से कम है, जो साल के इस समय के लिए सामान्य से क्रमश: 36 और 45 फीसदी कम है।

बढ़ता तापमान, गिरता जलस्तर फसलों के लिए पैदा कर सकता है मुश्किलें: बता दें कि भारत के कई हिस्सों में पहले ही दिन और रात का तापमान सामान्य से बहुत अधिक है। वहीं मानसून आने में अभी भी दो महीने से ज्यादा का समय है, ऐसे में जलाशयों का घटता जलस्तर रबी और खरीफके बीच उगाई जाने वाली गर्मियों की फसलों की पैदावार को प्रभावित कर सकता है। वहीं दक्षिणी क्षेत्र के जलाशयों में मौजूदा जलस्तर देश में दूसरा सबसे कम है। इस क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं, जिसमें कुल 43 जलाशय हैं। इनका मौजूदा जलस्तर कुल क्षमता का महज 41 फीसदी है। इसी तरह भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जलाशयों का जलस्तर उनकी क्षमता का 55 फीसदी है। वहीं मध्य क्षेत्र में यह आंकड़ा 49 फीसदी, जबकि पूर्वी क्षेत्र में 44 फीसदी रिकॉर्ड किया गया है। इस बीच सीडब्ल्यूसी के आंकड़ों में दर्ज 20 नदी घाटियों में से 14 में मौजूद जल भंडार उनकी क्षमता के आधी से भी कम था। इन 20 नदी बेसिनों में से गंगा अपनी सक्रिय क्षमता के 50 फीसदी पर है। वहीं गोदावरी में 48 फीसदी, नर्मदा में 47 फीसदी और कृष्णा में महज 34 फीसदी पानी ही बचा है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बोले-किसानों को 5 रुपए में दे रहे बिजली कनेक्शन

मप्र ने कृषि में किए कई नवाचार, इसलिए देश में अव्वल

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की उर्वर धरा में खेती-किसानी लाभ का व्यवसाय है। हमने इसी दिशा में काम किया। नई कृषि विधियों को अपनाया, कई नवाचार किए। यही कारण है कि आज मध्यप्रदेश कृषि विकास के मामले में पंजाब, हरियाणा और अन्य कई राज्यों से आगे निकलकर देश में अव्वल स्थान पर है। हम खेती-किसानी और किसान दोनों की समृद्धि के लिए प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री को समत्व भवन में नेशनल डिफेंस कॉलेज की ओर से मध्यप्रदेश आए अध्ययन यात्रा दल को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि एवं सहकारिता में मध्यप्रदेश में बीते दशकों में लगातार काम हुआ है। खेती के साथ-साथ सिंचाई पर भी हमने काम किया है। वित्त वर्ष 2002-03 तक मध्यप्रदेश में मात्र सात लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित थी। आज मध्यप्रदेश की 55 लाख से अधिक कृषि हेक्टेयर भूमि को हम सिंचित क्षेत्र में लेकर आए हैं। हम किसानों को सुविधा सम्पन्न बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। अगले तीन सालों में हमारी सरकार प्रदेश के 30 लाख किसानों को न केवल सोलर पम्प देगी, वरन् उनके द्वारा उत्पादित अतिरिक्त सोलर ऊर्जा का क्रय भी करेगी। इससे किसानों को दोहरा फायदा होगा। इसके अलावा हम किसानों को मात्र 5 रुपए की राशि पर बिजली कनेक्शन भी दे रहे हैं। मध्यप्रदेश ऊर्जा के मामले में भी आगे है। देश में सबसे सस्ती बिजली देने वाला प्रदेश मध्यप्रदेश है। दिल्ली मेट्रो भी मध्यप्रदेश की बिजली से चलायमान है।

- तीन साल में 30 लाख किसानों को दे देंगे सोलर पम्प, किसानों से बिजली भी खरीदेंगे
- दुग्ध उत्पादन में अभी हम तीसरे नंबर पर हैं, अगले चार साल में आएंगे पहले नंबर पर
- हम देश में सबसे सस्ती बिजली दे रहे हैं, दिल्ली मेट्रो भी चल रही मप्र से
- सरकार की नीतियों से किसान समृद्ध, स्व-सहायता समूहों से महिलाओं को भी मिला संबल

यात्रा पर आए दल ने की सौजन्य भेंट

मुख्यमंत्री से नेशनल डिफेंस कॉलेज (एनडीसी), नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रणनीति विषय पर आयोजित अध्ययन यात्रा के लिए मध्यप्रदेश राज्य की यात्रा के लिए आए दल ने सौजन्य भेंट की। देश के 5 मित्र देशों के प्रतिनिधि भी अध्ययन दल के साथ मध्यप्रदेश आए हैं। एनडीसी द्वारा पूरे देश के लिए ऐसे 8 अध्ययन समूह तय किए गए हैं, जिनमें से 16 सदस्यीय एक समूह मध्यप्रदेश की अध्ययन यात्रा पर है। मध्यप्रदेश आए यात्रा दल को यहां प्रदेश में कृषि एवं सहकारिता अध्ययन शीर्षक दिया गया है।

किसानों की समृद्धि बढ़ी

अध्ययन यात्रा दल ने बीते दिनों मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों का फील्ड विजिट कर कृषि एवं सहकारिता क्षेत्र में हुई प्रगति का अध्ययन किया और देखा कि मध्यप्रदेश ने इन दोनों क्षेत्रों में बेहतरीन प्रगति हासिल की है। अध्ययन दल ने पाया कि सरकार की नीतियों से किसानों की समृद्धि बढ़ी है। वहीं स्व-सहायता समूहों के जरिए प्रदेश में आजीविका विकास विशेषकर महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए अभूतपूर्व काम हुआ है।

दल अपने अनुभव साझा किए

यात्रा दल के सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में मध्यप्रदेश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, यह हमने खुद देखा है। कृषि के जरिए किसानों एवं स्व-सहायता समूहों के जरिए आजीविका विकास के लिए सरकार के प्रयास निःसंदेह प्रशंसनीय है। म.प्र. में शासन, प्रशासन की मदद से लोग खुद-ब-खुद जुड़कर अपनी आजीविका और जिंदगी की सफलता की कहानी खुद लिख रहे हैं। हमने मध्यप्रदेश में सामाजिक बदलाव (सोशल चेंज) देखा है।

भोपाल में औसतन दो लाख किलो रोज होगी खपत

खास नहीं रहेगा आम! पैदावार 80 प्रतिशत से ज्यादा होगी

भोपाल। जागत गांव हमार

फलों का राजा आम इस सीजन में खास नहीं, बल्कि आम रहेगा। यह वर्ष आम का ऑन ईयर है। इस कारण पिछले साल के मुकाबले इस बार आम की पैदावार 80त्न ज्यादा होगी। सिर्फ भोपाल में ही आम की औसतन 2 लाख किलो खपत होगी। आम पर पीएचडी कर चुके प्रोफेसर एवं प्रिंसिपल साइंटिस्ट एवं हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट डॉ. आरके जायसवाल बताते हैं इस बार आम की फसल पर मौसम की खास मेहरबानी रही। दिसंबर में तापमान अनुकूल रहने से फूल यानी बौर आने लगे थे। भोपाल समेत मध्य भारत में सीजन में आम की आवक का 15 मार्च से 15 जुलाई तक चक्र तय है। मार्च - अप्रैल में आंध्र प्रदेश कर्नाटक से, मई में मप्र महाराष्ट्र , गुजरात और पश्चिम बंगाल से आम की आवक होती है। फिर जून में यूपी, बिहार से और जुलाई में हिमाचल व कश्मीर के आम हमारे बाजार में पहुंचते हैं। इस बार इन इलाकों से आम की हर वैरायटी 15 दिन पहले बाजार में पहुंचेगी। सीजन में सबसे पहले बाजार में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से बादाम, तोतापरी, बेंगलोरा और बैंगन पल्ली किस्म के आम की आवक होती है। इसके बाद अन्य राज्यों के आम की आवक होती है। भोपाल के ईंटखेड़ी स्थित फल अनुसंधान केंद्र के सरकारी बगीचे की अलग-अलग वैरायटी के आम बाजार में जून में पहुंचने लगते हैं।

भोपाल में खपत का गणित

डॉ.जायसवाल के मुताबिक भोपाल में ऑन ईयर में रोजाना 15 से 20 ट्रक आम की आवक होती है। रोजाना कुल लगभग 200 टन आवक होती है। एक टन में 1000 किलो होते हैं। इस तरह सीजन में रोजाना करीब 2 लाख किलो आवक होती है। सीजन में इतनी खपत भोपाल में हो जाती है। थोक व्यापारी हरिओम खटीक भी यही बात कहते हुए बताते हैं इस बार आवक 15 दिन पहले होने लगी है। भोपाल में सीजन में रोजाना 200 टन माल खप जाता है।

आसानी से समझें

डॉ. जायसवाल बताते हैं उद्यानिकी के तय मापदंडों और आम की फलन चक्र के लिहाज से एक वर्ष ऑफ ईयर और अगला वर्ष ऑन ईयर होता है। ऑफ ईयर में आम की पैदावार 20 फीसदी होती है। ऑन ईयर में यह इससे 80 फीसदी ज्यादा यानी 100 फीसदी होती है। इस वजह से इस बार 80 फीसदी ज्यादा पैदावार होगी।

अगले खरीफ सीजन में खादों की नहीं होगी कमी

अगले खरीफ सीजन में खादों की नहीं होगी कमी, सभी उर्वरकों के उत्पादन में उछाल

भोपाल। जागत गांव हमार

फरवरी में प्रमुख खादों - यूरिया, डीएपी, एमओपी और कॉम्प्लेक्स - की बिक्री मासिक मांग से 11 प्रतिशत अधिक रही। यह लगातार तीसरा महीना है जब खादों की बिक्री मांग से अधिक रही है। यूरिया के आयात में कटौती के बीच, पिछले साल अक्टूबर-नवंबर के दौरान कम सप्लाई के कारण देश को खादों की गंभीर कमी का सामना करना पड़ा था। अब स्थिति में सुधार है और मांग से अधिक बिक्री दर्ज की जा रही है। जनवरी 2025 में बिक्री 33 प्रतिशत और दिसंबर 2024 में मांग अनुमान के मुकाबले 29 प्रतिशत अधिक रही। अक्टूबर 2024 में खाद की बिक्री मांग से 33 प्रतिशत कम रही और नवंबर में 6 प्रतिशत की गिरावट आई। ये दोनों महीने रबी सीजन में खादों के इस्तेमाल के लिए अहम महीने हैं।

एक्सपर्ट इस सुधार के पीछे सरकार की तैयारियों को वजह मानते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि पिछले साल बुवाई सीजन में खादों की कमी के बाद सरकार ने सबक सीखा और आगे हालात सुधारने के प्रयास किए। साल 2024 मध्य पूर्व में फैसी अशांति की वजह से खादों की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा था। इससे भारत में भी खादों की किल्लत देखी गई। एक एक्सपर्ट ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि कम से कम सरकार ने सबक सीखा है, क्योंकि पिछले त्योहारी सीजन में किसानों को एक बैग खाद खरीदने के लिए लंबी कतारों में खड़े होकर लाठियों का सामना करना पड़ा था। उम्मीद है कि आगामी खरीफ सीजन में संकट का दोहराव नहीं होगा।

यूरिया की बिक्री में उछाल

ताजा आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-फरवरी के दौरान यूरिया की बिक्री 371.19 लाख टन तक पहुंच गई, जो एक साल पहले 342.13 लाख टन से 8.5 फीसदी अधिक है। जबकि एमओपी की बिक्री 15.23 लाख टन से बढ़कर 20.42 लाख टन (34.1 फीसदी अधिक) और कॉम्प्लेक्स की बिक्री 112 लाख टन से बढ़कर 143.05 लाख टन (27.7 फीसदी अधिक) हो गई। केवल डीएपी की बिक्री 106.37 लाख टन से घटकर 93.47 लाख टन रह गई, जिसका मुख्य कारण नवंबर 2024 के मध्य तक इस खाद की कमी है। इन सभी चार प्रकार की खादों की चालू वित्त वर्ष में फरवरी तक कुल बिक्री 628.13 लाख टन दर्ज की गई है, जबकि एक साल पहले यह 575.73 लाख टन थी। वित्त वर्ष 2025 के अप्रैल-फरवरी के दौरान सभी खादों का उत्पादन 2.4 प्रतिशत बढ़कर 476.86 लाख टन हो गया।

यूरिया सब्सिडी भी बढ़ी

फरवरी तक 11 महीनों के दौरान देश में यूरिया आयात 51.69 लाख टन दर्ज किया गया, जबकि एक साल पहले यह 66.67 लाख टन था - यानी 22.5 प्रतिशत की गिरावट। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान रिकॉर्ड 98.28 लाख टन यूरिया आयात हुआ था। कुल खादों का आयात भी 11.6 प्रतिशत घटकर 141.86 लाख टन रह गया, जिसमें कॉम्प्लेक्स आयात घटकर 19.05 लाख टन (19.96 लीटर) और डीएपी 44.19 लाख टन (53.13 लीटर) रह गया। इस बीच, यूरिया सब्सिडी 119,414.43 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो 1,19,000 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से अधिक है, जबकि पोटाश और फास्फोरस 49,523.43 करोड़ रुपए (52,310 करोड़ संशोधित अनुमान के मुकाबले) तक पहुंच गई है, जो कुल मिलाकर 2024-25 के बजट (संशोधित अनुमान) में आवंटित 1,71,310 करोड़ रुपए का 98.6 प्रतिशत है।

भारत में गेहूं की बंपर पैदावार का अनुमानः केंद्र ने 115 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा

एमपी-यूपी में 150-175 रु. एमएसपी के ऊपर मिल रहा बोनस

भोपाल। जागत गांव हमार

भारत में इस साल गेहूं की बंपर पैदावार का अनुमान है। केंद्र ने 115 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इस बीच, अब कई प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में इसकी एमएसपी पर सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। इनमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। इन राज्यों में जल्दी फसल की बुवाई के कारण कटाई शुरू हो गई है और उपज मंडी तक पहुंचने लगी है। गौरतलब है कि केंद्र ने चालू मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए गेहूं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। पिछले मार्केटिंग सीजन में एमएसपी 2275 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसमें इस बार 150 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पहले 1 मार्च से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू की गई थी, लेकिन इसे कुछ दिन के लिए टाल दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि उस समय इन राज्यों में कई जगहों पर बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हो गई थी, जिसके कारण फसल में नमी जैसी समस्या होना तय था। ऐसे में किसानों को नमी के कारण कम दाम में फसल न बेचनी पड़े, इसलिए राज्य सरकारों ने खरीद को बाद में जारी करने का फैसला लिया।

मप्र में कीमतें गिरी, यूपी में खास असर नहीं

वहीं, एक नजर अगर गेहूं के मंडी भाव को देखें तो अब कीमतों में गिरावट दिखने लगी है। मध्य प्रदेश में कुछ समय पहले सामान्य तौर पर कीमतें 2800-2900 रुपए या इससे ज्यादा देखने को मिल रही थीं, लेकिन सरकारी खरीद की तारीख नजदीक आते-आते ये लगभग 2500 से 2600 रुपए प्रति क्विंटल तक आई गई, जो आम उपभोक्ता के लिहाज से सही मानी जा रही हैं। हालांकि, उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में कीमतें अभी भी 2800-2900 रुपए प्रति क्विंटल देखी जा रही है और खास कमी नहीं देखी गई। केंद्र ने गेहूं का स्टॉक बढ़ाने की कोशिश में विभिन्न राज्यों से 31 मिलियन टन खरीद का लक्ष्य तय किया है।

मप्र में 175 रुपए/क्विंटल बोनस

जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश में 15 मार्च से, उत्तर प्रदेश में 17 मार्च से दोबारा गेहूं खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और किसान उपार्जन केंद्रो पर उपज लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं, राजस्थान में 10 मार्च से सरकारी खरीद शुरू हुई, जहां एमएसपी के अतिरिक्त 150 रुपए प्रतं क्विंटल बोनस दिया जा रहा है, यानी किसानों को 2575 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में गेहूं पर एमएसपी के अलावा 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जा रहा है। ऐसे में किसानों को 2600 रुपए प्रति क्विंटल रुपए कीमत मिल रही है। हालांकि, नया एमएसपी आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल 2025 से मान्य है. मध्य प्रदेश में अब तक 10 लाख के करीब किसान गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जबकि अनुमान है कि 5 लाख किसान और जुड़ सकते हैं।

-शिवराज ने खेती पर मोदी सरकार का रखा विजन

अच्छे दिन! दलहन-तिलहन में आत्मनिर्भर बनेगा देश

भोपाल। जागत गांव हमार

खेती के क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। इसे लेकर सरकार ने किसानों और कृषि के लिए रोडमैप बनाया है। इसका एक विजन तैयार किया गया है। मोदी सरकार के इस विजन के बारे में बताते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार किसान कल्याण के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। कृषि सेक्टर इस देश की रीढ़ है और किसान इसकी आत्मा है। तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हुए एक विजन दिया है, जिसमें कृषि सेक्टर का अहम योगदान रहेगा। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जी, का भारत को ग्लोबल फूड बास्केट बनाने का संकल्प है, जिसमें देश के प्रत्येक नागरिकों के डाइनिंग टेबल पर भारत का कृषि उत्पाद अवश्य पहुंचे। कृषि मंत्री ने कहा, विजन अंतर्गत भारत के कृषि सेक्टर को वर्तमान समय के 2.4 से बढ़ाकर 10 फीसदी से अधिक करने का लक्ष्य है, जिसके लिए सभी मिलकर काम कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का लक्ष्य है कि कृषि सेक्टर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक तो बनाएं ही, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए, नागरिकों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करें।

चर्चा के बाद लागू कर रहे नीतियां

शिवराज ने कहा, कृषि सेक्टर की हमारी नीतियां सभी हितधारकों के साथ चर्चा करते हुए निर्धारित की जा रही हैं और उसमें बदलाव और सुधार भी राज्य सरकारों, किसान संगठनों और कृषि सेक्टर से जुड़े अन्य सभी हितधारकों के साथ चर्चा करके किया जाता हैं। कृषि मंत्री ने कहा, सभी मिलकर देश के अन्नदाता को आर्थिक रूप से समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए कृषि सेक्टर के विकास में साझा प्रयास करेंगे तो निश्चित ही विकसित भारत के मिशन में महत्वपूर्ण योगदान होगा।

नीतियां इन लक्ष्यों पर भी केंद्रित रहेंगी

- गेहूं-धान की आत्मनिर्भरता के बाद दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना
- किसानों को नवीन बीज, तकनीक उपलब्ध कराना ताकि वे फसल उत्पादकता और आय बढ़ा सकें
- विशेषकर औद्यानिक फसलों में रिटेल मूल्य का ज्यादा-से-ज्यादा हिस्सा किसानों को उपलब्ध हो
- पोस्ट हार्वेस्ट हानि को न्यूनतम करते हुए, वैल्यू एडिशन की अवस्थापना सुनिश्चित की जा सके
- मृदा स्वास्थ्य को बेहतर करने की नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके
- वैज्ञानिकों द्वारा नवीन तकनीक और बीजों को त्वरित गति से किसानों तक पहुंचाया जा सके
- उत्पादकता, उत्पादन और विविधीकरण में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना

प्रेजेंटेशन में बुरहानपुर के केले और देवास के खुरचन की बताई विशेषता

बुरहानुपर के केले में मिनरल्स का भंडार

जीआई टैग के लिए प्रजेंटेशन में बताईं खूबियां

-जानकारी लेकर दिल्ली लौटी जीआई टैग टीम, जल्द आ सकता है परिणाम

-अगर इसे जीआई टैग मिला तो इसके एक्सपोर्ट में कई गुना की वृद्धि संभव

बुरहानपुर। जागत गांव हमार

करीब दो साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद उज्जैन में जीआई टैग के लिए प्रेजेंटेशन बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश के सोलह से ज्यादा जिलों के अधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन दस जिलों के अधिकारी ही शामिल हुए। साथ ही केंद्र सरकार की टीम और जीआई टैग मप्र के डायरेक्टर लक्ष्मीकांत दीक्षित मौजूद थे। बैठक में शामिल बुरहानपुर जिले के विज्ञानिक और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने केले की विशेषता बताई। इसके साथ ही देवास जिले से पहुंचे अधिकारियों ने वहां के खुरचन (मलाई से बना मिष्ठान) और गुलाब जामुन की विशेषता बताई। इसके अलावा जीआई टैग के लिए नरसिंहपुर के बैगन व इमली और इंदौर के आलू को भी शामिल किया गया है। सभी जिलों के अधिकारियों ने अपने उत्पादों की विशेषता, गुणवत्ता और उनमें मौजूद तत्वों के संबंध में जानकारी दी। केंद्र से आई टीम प्रेजेंटेशन के दौरान सामने आए तथ्य व जानकारी लेकर दिल्ली रवाना हो गई है। इस बैठक को पूरी तरह गोपनीय रखा गया था। बताया जा रहा है कि जल्द ही इस प्रेजेंटेशन का परिणाम आ सकता है। यदि बुरहानपुर के केले को जीआई टैग मिला तो इसके एक्सपोर्ट में कई गुना की वृद्धि संभव है।

वर्ष 1960 से शुरू केले का उत्पादन

जिले में केले का उत्पादन वर्ष 1960 से शुरू हुआ था। पहली बार जलगांव से बैलगाड़ी में टिश्यू कल्चर लाकर पांच एकड़ खेत में फसल लगाई गई थी। इसके बाद धीरे-धीरे अन्य किसानों ने फसल लगाना शुरू किया। इससे पहले तक जिले में मोसम्बी और संतरे की खेती की जाती थी। यह जिला चारों ओर से पहाड़ों से घिरा है। केला उत्पादन के लिए जलवायु पूरी तरह उपयुक्त है।

छब्बीस हजार हेक्टेयर में होता है केला

जिले में 26 हजार हेक्टेयर में केले का उत्पादन होता है। इस काम में 16 हजार से ज्यादा किसान सक्रिय हैं। चार प्रमुख बिंदुओं पर प्रजेंटेशन तैयार किया था। इनमें जिले में केले का इतिहास, मिट्टी की गुणवत्ता, जलवायु और पोषक तत्व शामिल थे। केले को जीआई टैग प्रदान करने के लिए वर्ष 2023 में आवेदन किया गया था। अब जाकर जीआई टैगिंग के लिए बैठक बुलाई गई। उल्लेखनीय है कि बुरहानपुर का केला स्वाद और गुणवत्ता में हमेशा से बेहतर रहा है। यही वजह है कि इसकी मांग देश के कई राज्यों के साथ खाड़ी देशों तक है।

-मंत्री राजपूत बोले-धान और गेहूं उपार्जन में गड़बड़ी रोकने बनेगा एकीकृत निगरानी तंत्र

खाद्य मंत्री ने एसीएस-आयुक्त को दिए निर्देश, मैदानी गड़बड़ी रोकने करें कठोर कार्रवाई

उपार्जन, परिवहन-भंडारण में निगरानी के लिए बनेगा कंट्रोल कमांड सेंटर

भोपाल।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि धान और गेहूं उपार्जन, परिवहन और भण्डारण में सामने आने वाली गड़बडियों को रोकने के लिए एकीकृत निगरानी तंत्र जल्द विकसित करें। खाद्य मंत्री ने अपर मुख्य सचिव खाद्य एवं आयुक्त खाद्य को दिए निर्देश में कहा कि है धान और चावल के मिलिंग और परिवहन के दौरान वाहनों में जीपीएस सिस्टम आवश्यक रूप से लगवाने के साथ उसकी मॉनिटरिंग भी करें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि मुख्यालय स्तर पर कन्ट्रोल कमांड सेन्टर बनाया जाए जिससे खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम एवं वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरे प्रदेश में भण्डारित किए गए उपार्जित धान एवं गेहूं और चावल की मात्रा, परिवहन और मिलिंग की जानकारी एक ही क्लिक पर उपलब्ध हो जाए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा अनुरूप खाद्य विभाग में जीरो टॉरलेंस की नीति के पारदर्शी तरीके से क्रियान्वयन के लिए खाद्य मंत्री राजपूत हर संभव कोशिश कर रहे हैं।

गौरतलब है कि खाद्य मंत्री राजपूत ने विधानसभा में सदन को आश्वस्त किया था कि उपार्जन, परिवहन, भंडारण में गड़बड़ी रोकने के लिए एकीकृत प्रणाली विकसित कर होने वाली गड़बड़ियों पर लगाम कसेंगें। दरअसल सहकारिता विभाग के सहयोग से मिलकर गड़बड़ी करने वाली समितियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई जारी रखेंगे। मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया था कि जिन जिलों में समितियों में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा किसी भी प्रकार की गड़बड़ियां सामने आई है उन पर कठोर कार्रवाई की जाएंगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

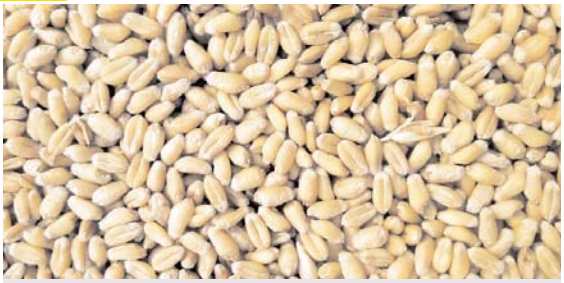

रैंडम जांच के निर्देश

प्रदेश में खरीफ उपार्जन वर्ष 2024-25 के तहत उपार्जित धान की मिलिंग का कार्य विभिन्न मिलर्स के माध्यम से प्रक्रियाधीन है। खाद्य मंत्री राजपूत ने प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम को 11 फरवरी 2025 को निर्देश दिये थे कि धान की मिलिंग कार्य उपरांत मानक गुणवत्ता के चावल प्राप्त करने के लिए नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा मुख्यालय स्तर पर एक दल गठित कर मिलिंग के दौरान समय-समय पर सीएमआर की रैंडम जांच सुनिश्चित करें।

जांच के लिए 3 सदस्यीय दल गठित

खाद्य मंत्री राजपूत ने बताया कि को लिखी गई नोटशीट के संबंध में खरीफ उपार्जन वर्ष 2024-25 में धान की मिलिंग उपरांत चावल की गुणवत्ता भारत शासन के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए एक 3 सदस्यीय दल नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा गठित किया गया है। टीम में मुख्यालय में पदस्थ सहायक महाप्रबंधक (परिदान), सहायक महाप्रबंधक, गुणवत्ता नियंत्रक को शामिल किया गया है। यह समिति समय-समय पर जिलों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सामने आने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के साथ तत्समय वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएंगी।

गेंहू खरीदी में महिलाओं की भागीदारी होगी सुनिश्चित

इधर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेंहू के उपार्जन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिला स्व-सहायता समूहों/ग्राम संगठकों को कार्य देने का प्रावधान उपार्जन नीति में किया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि महिला स्व-सहायता समूहों/ग्राम संगठकों को उपार्जन कार्य देने के लिए प्रक्रिया निर्धारित कर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूहों/ग्राम संगठकों का एक वर्ष पूर्व का पंजीयन होना चाहिए। महिला स्व-सहायता समूहों/ग्राम संगठकों के बैंक खाते में न्यूनतम 2 लाख रुपए जमा हों। समूह द्वारा विगत एक वर्ष में नियमित रूप से बैठकों का जायोजन किया गया हो। समूह में समस्त सदस्य/पदाधिकारी महिलाएं हो। विगत वर्षों में उपार्जन कार्य में कोई अनियमितता नहीं की गयी हो और महिला स्व-सहायता समूहों/ग्राम संगठकों को उपार्जन कार्य देने के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अनुशंसा जरूरी है। समूहों को पंजीयन प्रमाण-पत्र, विगत 6 माह के बचत खाते का बैंक स्टेटमेंट, विगत 3 माह की बैठकों का कार्यवाही विवरण और आवश्यक राशि की उपलब्धता का प्रमाण सहित अन्य जरूरी दस्तावेज देने होंगे। उपार्जन कार्य के लिए महिला स्व-सहायता समूहों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। महिला स्व-सहायता समूहों/ग्राम संगठकों को उपार्जन कार्य के लिए विभाग द्वारा उपार्जन एवं पंजीयन की अवधि के लिये कम्प्यूटर ऑपरेटर का मानदेय दिया जायेगा।

-मोहनपुरा-कुंडालिया को सर्वश्रेष्ठ समन्वित जल संसाधन प्रबंधन पुरस्कार

जल संसाधन के समुचित प्रबंधन से सिंचाई रकबे में हो रहा इजाफा

भोपाल।

जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में नवीन सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण और जल संसाधन के समुचित प्रबंधन से सिंचाई रकबे में निरंतर वृद्धि हो रही है। हर खेत तक पानी पहुंचाना प्रदेश सरकार का संकल्प है। मंत्री ने कहा कि यह प्रसन्नता और गौरव का विषय है कि राजगढ़ जिले की मोहनपुरा-कुंडालिया सिंचाई परियोजना को जल संसाधनों के कुशल उपयोग, जल संरक्षण और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए सीबीआईपी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पॉवर) अवॉर्ड्स- 2024 में सर्वश्रेष्ठ समन्वित जल संसाधन प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके लिए विभागीय अमला तथा क्षेत्र के किसान बधाई के पात्र हैं। पुरस्कार नई दिल्ली में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरीगेशन एंड पॉवर के ज्यूरी सदस्य एके दिनकर, घनश्याम प्रसाद एवं डॉ. एमके सिन्हा द्वारा गत दिवस दिया गया है। इसे मुख्य अभियंता एवं परियोजना निदेशक जीपी सिलावट, अधीक्षण यंत्री एवं परियोजना प्रशासक विकास राजोरिया, परियोजना निदेशक शुभंकर बिस्वास ने प्राप्त किया। मंत्री सिलावट ने कहा कि यह पुरस्कार मध्यप्रदेश की अभिनव जल प्रबंधन प्रणाली और सतत कृषि विकास में योगदान को मान्यता प्रदान करता है। यह सम्मान राज्य सरकार की दूरदर्शी जल प्रबंधन नीतियों और कुशल कार्यान्वयन का परिणाम है। पुरस्कार जल संरक्षण और आधुनिक सिंचाई प्रणालियों के विस्तार को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने बताया कि मोहनपुरा-कुंडालिया सिंचाई परियोजना की सबसे बड़ी खासियत रिजर्वायर से सीधे खेत तक पानी पहुंचाने की नवीनतम तकनीक है। इस तकनीक में पारंपरिक नहरों के बजाय प्रेशराइज्ड पाइप लाइन नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, जिससे पानी बिना किसी रिसाव और वाष्पीकरण के सीधे खेतों तक पहुंचता है। पाइप लाइन आधारित सिंचाई प्रणाली से जलाशय से निकलने वाला पानी बिना खुली नहरों के सीधे किसानों तक पाइपों के माध्यम से पहुंचाया जाता है, जिससे पानी का अपव्यय न के बराबर होता है। मंत्री सिलावट ने कहा कि भू-जल स्तर संतुलन, पर्यावरणीय संतुलन, जलभराव, मिट्टी कटाव और जैव विविधता संरक्षण के साथ ही जल प्रबंधन में यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मोहनपुरा-कुंडालिया सिंचाई परियोजना ने मध्यप्रदेश को जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बना दिया है। इस पुरस्कार से यह सिद्ध होता है कि नवीनतम तकनीकों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जल संसाधनों का उपयोग किया जाए, तो जल संरक्षण और सतत कृषि विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है।

इन नवाचारों से मिला पुरस्कार

ऊर्जा दक्षताः पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए प्राकृतिक ढलान और पम्पिंग सिस्टम का उपयोग किया, इससे कम ऊर्जा खपत के साथ किसानों को सिंचाई में अतिरिक्त लागत नहीं लगती। सिंचाई का समावेशः खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक को बढ़ावा दिया, जिससे किसान कम पानी में अधिक उत्पादन कर सकते हैं।

जलभराव कीरोकथामः पारंपरिक नहरों में होने वाले जलभराव और मिट्टी के कटाव की समस्या इस प्रणाली में समाप्त हो गई, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बना रहता।

जल उपलब्धताः यह प्रणाली रबी और खरीफ दोनों सीजन में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, जिससे किसान अधिक आत्मनिर्भर बनते हैं।

सफल क्रियान्वयन

परियोजना में जल संसाधनों के समुचित और समग्र प्रबंधन का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आईडब्लूआरएम के तहत जल की उपलब्धता, कुशल उपयोग और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित की गई है। पारंपरिक नहरों की जगह प्रेशराइज्ड पाइप लाइनों से जल सप्लाई की। सभी जल उपभोक्ता ओं को परियोजना से कृषि, पीने के पानी का समान वितरण किया। साथ ही उद्योगों के लिए भी जल आरक्षित किया गया। किसानों को आधुनिक कृषि और जल प्रबंधन तकनीकों की जानकारी दी गई, ताकि वे जल का बेहतर उपयोग कर अधिक उत्पादकता हासिल कर सकें।

-फसल की लागत निकालना भी मुश्किल

मध्य प्रदेश में 2 रुपए किलो तक गिरे टमाटर

भोपाल।

मध्य प्रदेश में टमाटर की खेती करने वाले किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बाजार में नई फसल की बंपर आवक के कारण इस सब्जी का थोक मूल्य 2 रुपए प्रति किलोग्राम तक गिर गया है। किसान संगठनों ने मांग की है कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल उचित कदम उठाए और किसानों को राहत देने के लिए सरकार मदद करे। इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर फल एवं सब्जी मंडी राज्य की सबसे बड़ी थोक मंडियों में से एक है। करीब 130 किलोमीटर दूर खंडवा जिले से मंडी पहुंचे किसान धीरज रायकवार ने कहा कि टमाटर का थोक भाव गिरकर 2 रुपए प्रति किलो पर आ गया है। इस भाव पर तो हम फसल की लागत भी नहीं निकाल पाएंगे।

किसानों की शिकायत- किसान धीरज रायकार ने दावा किया कि कुछ किसान टमाटर की बची हुई खेप को बाजार में फेंकने को मजबूर हैं। रायकवार ने कहा, पिछले साल टमाटर की अच्छी कीमत मिलने के कारण किसानों ने बड़े पैमाने पर इसकी खेती करने का फैसला किया। इस बार बंपर उत्पादन के कारण बाजार में टमाटर की भारी आवक है, जिससे कीमतों में गिरावट आई है।

2 लाख का कर्ज लिया था,

पड़ोसी धार जिले के किसान दिनेश मुवेल ने कहा कि उन्होंने दो एकड़ में टमाटर की खेती के लिए 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन अब गिरती कीमतों के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनकी तरह और भी कई किसान हैं जो टमाटर की गिरती कीमतों से परेशान हैं और लागत को लेकर घोर चिंता में हैं।

सरकार से मदद की गुहार

पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा-निमाड़ क्षेत्र में संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक राम स्वरूप मंत्री ने मांग की है कि राज्य सरकार किसानों से टमाटर उचित मूल्य पर खरीदे, ताकि नुकसान से बचा जा सके। उन्होंने कहा,मोर्चा सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। भारतीय किसान-मजदूर सेना के अध्यक्ष बबलू जाधव ने कहा कि राज्य के दूरदराज के इलाकों में टमाटर जैसी जल्दी खराब होने वाली फसलों के लिए कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग सुविधाओं की कमी है, जिसके कारण किसान अपनी फसल

-लागत 10601 करोड़, लाखों किसानों को फायदा

सरकार ने अमोनिया यूरिया कांप्लेक्स को मंजूरी दी, लाखों किसानों को होगा फायदा

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। इसमें दो फैसले किसानों से जुड़े हैं। ये दो फैसले यूरिया प्लांट और देश में डेयरी के विकास से जुड़े हैं। इन दोनों फैसलों से देश के लाखों किसानों को फायदा होगा। असम में यूरिया प्लांट की मांग लंबे दिनों से चली आ रही थी जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। उसी तरह, पशुपालन के महत्व को देखते हुए डेयरी विकास से जुड़े काम में सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने जा रही है जिसका ऐलान कैबिनेट बैठक में किया गया। कैबिनेट ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कैबिनेट ने डेयरी विकास के लिए संशोधित राष्ट्रीय कार्यक्रम को मंजूरी दी है। संशोधित एनपीडीडी, एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसे अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए के साथ बढ़ाया गया है, जिससे 15वें वित्त आयोग (2021-22 से 2025-26) की अवधि के लिए कुल बजट 2790 करोड़ रुपए हो गया है। यह पहल डेयरी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और विस्तार पर केंद्रित है, जिससे इस क्षेत्र की वृद्धि और विकास होगा।

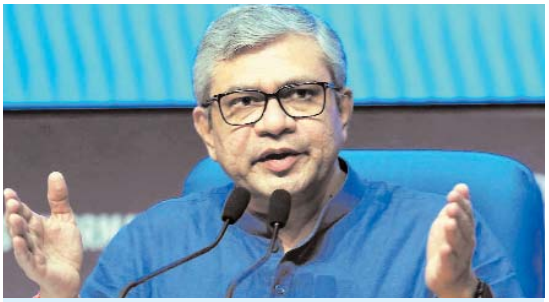

डेयरी विकास पर सरकार का फोकस

वैष्णव ने डेयरी विकास के बारे में कहा कि सरकार का ध्यान कोऑपरेटिव के माध्यम से डेयरी के विकास पर केंद्रित है। इस प्रोजेक्ट में किसानों को दूध उत्पादन कंपनी खोलने की सुविधा दी जाएगी। इसमें सबसे बड़ा फोकस डेयरी के जरिये दूध की सरकारी खरीद और दूध के प्रोडक्ट में वैल्यू एडीशन करने पर है। वैष्णव ने बताया कि देश में कोऑपरेटिव कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका नमूना है कि 2013-14 में 342 लाख किलो दूध हर दिन उत्पादन होता था जो 2023-24 में बढ़कर 6628 लाख किलो प्रति दिन हो गया। दस साल पहले देश में जहां देश में कोऑपरेटिव के जरिये हर दिन 471 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग होती थी। वहीं अब बढ़कर 1074 लाख लीटर प्रति दिन हो गई है।

सरकार के बड़े फैसले

दूसरे बड़े फैसले के बारे में कहा, कैबिनेट ने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, नामरूप, असम के मौजूदा कॉम्प्लेक्स में एक नया ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप आईवी फर्टिलाइजर प्लांट लगाने को मंजूरी दी है। इस परियोजना से उत्तरपूर्व क्षेत्र में यूरिया की उपलब्धता में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। इस प्लांट से असम, प. बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों को भी लाभ होगा। इसके अलावा, कैबिनेट ने वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए बढ़ाए गए आवंटन के साथ संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लागू करने को मंजूरी दी। यह मिशन कृत्रिम गर्भाधान और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से दूध उत्पादन की उत्पादकता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

यूरिया प्लांट का बड़ा फायदा

वैष्णव ने असम के यूरिया प्लांट के बारे में बताया कि नारूप अमोनिया यूरिया प्लांट प्रोजेक्ट में एक जॉइंट वेंचर बनेगा जिसमें असम सरकार, बीवीएफसीएल, एचयूआरएल, एनएफएल और ऑयल इंडिया लिमिटेड शामिल होंगे। इन सभी कंपनियों के जॉइंट वेंचर और 10601 करोड़ रुपए के निवेश से यूरिया का निर्माण होगा। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से असम सहित पूरे उत्तरपूर्व में बड़ा बदलाव आएगा जिसमें यूरिया की उपलब्धता बढ़ेगी। उत्तर पूर्व के राज्यों के अलावा बंगाल को इस प्रोजेक्ट का लाभ मिलेगा। यूरिया प्लांट के लिए गैस की अधिक जरूरत होगी जिसे उत्तरपूर्वी राज्यों से मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा गैस ग्रिड से भी यूरिया प्लांट को गैसी सप्लाई की जाएगी। यह प्लांट 48 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। इस यूरिया प्लांट के लिए असम सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस प्लांट के बनने से पूरे उत्तरपूर्व में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही यूरिया की सप्लाई बढ़ेगी. आगे चलकर इस प्लांट से यूरिया का निर्यात हो सकेगा। इस प्लांट से म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश को यूरिया का निर्यात हो सकता है। घरेलू स्तर पर बात करें तो इस प्लांट के बनने से कामरूप और असम के आसपास के राज्यों में यूरिया ढुलाई का खर्च बचेगा।

एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने पर केंद्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह बोले

भारत का प्याज अब दुनिया में पहुंचेगा

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो प्याज उत्पादक किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, जिससे किसानों को बेहतर लाभ मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें किसान बहुत पहले से प्याज पर से एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग कर रहे थे। किसानों का कहना था कि एक्सपोर्ट ड्यूटी अधिक होने से उनकी उपज को सही दाम नहीं मिल रहे हैं। यहां तक कि घरेलू बाजार में भी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है। एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने को लेकर नासिक आसपास के किसानों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था।

किसानों ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से ड्यूटी हटाने की मांग की थी। शिवराज ने बताया कि पहले प्याज पर 40 प्रतिशत एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, जिससे किसानों को उनके उत्पाद की उचित कीमत नहीं मिल पाती थी, लेकिन सरकार ने यह महसूस किया कि प्याज के दाम गिरने से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी को 40 से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया। अब, सरकार ने इस 20 प्रतिशत ड्यूटी को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, जिससे अब प्याज का निर्यात बिना किसी शुल्क के किया जा सकेगा। इससे भारतीय प्याज वैश्विक बाजार में बिना किसी अतिरिक्त लागत के पहुंचेगा, और किसानों को उनके मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा।

ऑपरेटर ने दबाव में की आत्महत्या, राजमणि सिंह बघेल ने दी सफाई

» एमपी धान खरीद घोटाला-ऑपरेटर के परिजन का आरोप

» आईजी से शिकायत, भाजयुमो ग्रामीण जिलाध्यक्ष का नाम

जबलपुर। धान खरीदी घोटाले के आरोपी ऑपरेटर पनागर के ग्राम बम्होरी निवासी गणेश तिवारी की आत्महत्या को लेकर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वह जिस समिति के कार्य करता था, उसके अध्यक्ष भाजयुमो के जिलाध्यक्ष राजमणि सिंह बघेल, आशु सोनी एवं प्रिंस उपाध्याय व अन्य दो सदस्यों की प्रताड़ना से तंग आकर उसके आत्महत्या करने की शिकायत की है। मृतक गणेश के पिता संतोष तिवारी ने आईजी को शिकायत सौंपी है। शिकायत बताया कि उनका पुत्र गणेश वर्ष 2024 में गांधीग्राम सेवा सहकारी समिति में धान खरीदी ऑपरेटर का कार्य करता था। गत वर्ष उसे ग्राम धमधा स्थित अर्नवी वेयर हाउस में ऑपरेटर बनाया गया। पिता का आरोप है कि उनके बेटे को अधिक अनुभव नहीं था, जिसका फायदा समिति प्रबंधक व अन्य ने उठाया। आरोप है कि समिति प्रबंधक राजमणि सिंह बघेल व उसके साथियों ने गणेश से आईडी पासवर्ड लेकर फर्जी धान खरीदी की और स्टॉक कम बताकर गणेश से गबन की राशि भरने कहा। दबाव बनाकर गणेश से 30 लाख ले लिए।

जागत गांव हमार, सलाहकार मंडल

1. **प्रो. डा. केआर मौर्य, पूर्व कुलपति,** राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसासमस्तीपुर (बिहार) एवं महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान) ईमेल-kuber.ram@gmail.com, मोबा- 7985680406
2. **प्रो. डा. गैब्रियल लाल, प्रोफेसर,** आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग सैम हिंगिन बॉटम यूनिवर्सिटी आफएग्रीकल्चर, टेक्नालोजी एंड साइंसेज, प्रयागराज, उप्र। ईमेल- द्दुद्बड्डह्मiyal.lal @shiats.edu.in, मोबा- 7052657380
3. **डा. वीरेन्द्र कुमार,** प्रोफेसर एंड हेड, पौध रोग विज्ञान विभाग, डा. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय परिसर ढोली, मुजफ्फरपुर बिहार। ईमेल- birendraray@gmail.com मोबा- 8210231304
4. **डा. नरेश चन्द्र गुप्ता, वैज्ञानिक,** मृदा विज्ञान, कृषि महाविद्यालय बिरसा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कॉके, रॉची झारखण्ड। ईमेल- ncguptabau@gmail.com, मोबा- 8789708210
5. **डा. देवेंद्र पाटिल, वैज्ञानिक** (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, सीहोर (मध्यप्रदेश) सेवनिया, इछावर, सिहोर (मप्र) ईमेल- dpatil889@gmail.com, मोबा- 8827176184
6. **डा. आशुतोष कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर,** एग्री विजनेस मैनेजमेंटकृषि अर्थशास्त्र विभाग, एकेएस,विश्वविद्यालय, सतना, मप्र ईमेल- kumar.ashu777@gmail.com, मोबा- 8840014901
7. **डा. बिनीता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर** आनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग एकेएस विश्वविद्यालय, सतना, मप्र ईमेल- singhvineeta123@gmail.com, मोबा- 8840028144
8. **डा. आरके शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर,** परिजीवी विज्ञान विभाग, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, बिहार। ईमेल- drrksharmabvc@gmail.com, मोबा- 9430202793
9. **डा. दीपक कुमार, सहायक प्राध्यापक,** मृदा एवं जल संरक्षण अभियंत्रिकी विभाग, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर, उत्तराखण्ड। ईमेल- deepak.swce.cot.gbpuat@gmail.com, मोबा- 7817889836
10. **डा. भारती उपाध्याय, विषय वस्तु विशेषज्ञ** (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, विरौली, समस्तीपुर, बिहार। ईमेल-bharati.upadhya@rpcau.ac.in, मोबा- 8473947670
11. **रोमा वर्मा,** सब्जी विज्ञान विभाग महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं् वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़। ईमेल- romaverma35371@gmail.com, मोबा- 6267535371

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। **संपादकः** अजय कुमार द्विवेदी, **स्थानीय संपादकः अरविंद मिश्रा, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)